



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत बिल्व का पौधा लगाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने चाहिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने जोधपुर हाउस में बिल्व का पौधा लगाया

दिल्ली में पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने रिफाइनरी के काम में तेजी लाने की बात कही

नई दिल्ली/जयपुर, 3 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत बिल्व का पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिल्व जैसे पौधे धार्मिक और औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाने चाहिए।

शर्मा ने रविवार को नई दिल्ली के

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन तथा विरासत से जुड़े पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जायेगा। प्राचीन हवेलियों और हेरिटेज सम्पत्तियों की सूची बनवाई गई है तथा उनके उचित रखरखाव के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी।**

बीकानेर हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि हमारी सरकार राजस्थान के चर्हुमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है। राजस्थान रिफाइनरी

के काम में तीव्रता लाकर यहां बनने वाले बाय-प्रोडक्ट्स को संसाधित करके इससे जुड़े उद्योगों की स्थापना पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम

किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन और हमारी विरासत से जुड़े पर्यटन स्थल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्राचीन हवेलियों और हेरिटेज संपत्तियों की सूची बनवाई गई है। इनके उचित रखरखाव के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी।

गडकरी के घर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
पुलिस और डॉग स्कॉयड की टीम ने गडकरी के घर मेंसर्च ऑपरेशन भी चलाया।

कुछ घंटों बाद गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम उमेश विष्णु राउत है। उमेश विष्णु राउत मेडिकल चौक स्थित एक देसी शराब की दुकान पर काम करता है। पुलिस ने उसे नागपुर के बीमा दवाखाना के पास से गिरफ्तार किया है।

बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में ही मौजूद हैं। पुलिस की टीम अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर धमकी देने के पीछे की संशा को जानना चाहेगी कि कहीं इस घटना में कोई और एंगल तो नहीं है।

सरकार ने 35 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अधिक वसूली गई राशि को वसूलना शामिल होगा। एनपीपीए ने साफ किया है कि निर्धारित मूल्यों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं है, जिसे लागू होने पर जोड़ा जा सकता है। निर्माताओं को सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा, ईटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से फॉर्म में अपडेटेड प्राइस लिस्ट जारी करनी होगी और एनपीपीए तथा राज्य औषधि नियंत्रकों को जानकारी देनी होगी। स्पेसिफाइड फॉर्मूलेशन और निर्माताओं के लिए जारी किए गए किसी भी पूर्व मूल्य आदेश को इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

‘योगी के कैबिनेट मंत्री राजभर बिहार में भाजपा पर दबाव बना रहे हैं’

वे बिहार विधानसभा चुनाव में सम्मानजनक सीटों पर गठबंधन करना चाहते हैं

लखनऊ, 3 अगस्त। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अब नए समीकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके संकेत उस समय मिलने शुरू हो गए जब उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो सारे विकल्प खुले हुए हैं।

दरअसल, भाजपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बिहार चुनाव लड़ने के लिए गैर-भाजपा दलों के साथ तीसरा मोर्चा बनाने के संकेत

■ **राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी कई वर्षों से बिहार में सक्रिय है, इसलिए वे विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं।**

देकर अपनी राजनीतिक ताकत फिर से दिखानी शुरू कर दी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में कहा अगर बिहार में भाजपा के साथ हमारा गठबंधन नहीं होता है, तो हम सभी विकल्प खुले रखेंगे।

योगी सरकार में मंत्री राजभर ने

कहा कि उनकी पार्टी प्रशंत किशोर की जन सुराज पार्टी में सुनवाई के लिए याचिका ऐसे समय में दाखिल की गई है जब राज्य और केन्द्र की जांच एजेंसियों, ईडी तथा आर्थिक अपराध शाखा सहित कई केंद्रीय जांच एजेंसियों ने संबंधित मामलों की जांच तेज कर दी है।

यह याचिका सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लिस्टिंग की गई है। इसके अलावा बघेल और उनके बेटे ने सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही जांचों की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि सीबीआई और ईडी

को छत्तीसगढ़ में जांच करने का अधिकार किस आधार पर मिला, जब राज्य सरकार ने पहले ही उनकी आम सहमति वापस ले ली थी।

सब इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति क्या और कैसी बनती है। हम विधानसभा में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, जहां हम पिछले कई वर्षों से सक्रिय हैं। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि राजभर सीवान, चंपारण, सारण, गोपालगंज और बक्सर के कुछ इलाकों में सम्मानजनक सीटों के लिए भाजपा से कड़ी मोलभाव कर रहे हैं जहां राजभर, राजवंशी, राजघोषी और भर समुदायों की अच्छी-खासी मौजूदगी है। पार्टी का लक्ष्य पटवा और मंडल जैसी जातियों को भी एकजुट करना है।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर सेना के अधिकारी व एयरलाइन कर्मचारियों में मारपीट

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई

श्रीनगर, 3 अगस्त। श्रीनगर में हवाई अड्डे पर सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक निजी एयरलाइंस के चार कर्मचारियों को कथित तौर पर बुरी तरह पीटने की घटना के प्रकाश में आने के बाद एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

एयरलाइंस स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बताया कि कश्मीर में तैनात एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने 26 जुलाई को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उसके चार कर्मचारियों पर कथित तौर पर तब हमला बोल दिया जब उन्होंने सामान के किराए के भुगतान का अनुरोध किया। इस मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज

■ **एयर लाइन्स के अनुसार, सेना अधिकारी के सामान का वजन अधिक था तथा उनसे बोर्डिंग गेट पर अतिरिक्त भार के भुगतान के लिए कहा गया था।**

■ **सेना ने कहा कि वह जाँच में पूरा सहयोग करेगी।**

कराई है और नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यात्री का नाम काली सूची (नो-फ्लाई) में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

एयरलाइंस ने कहा कि उसने घटना का सीसीटीवी फुटेज हासिल करके पुलिस को सौंप दिया है और वह इस मामले की पूरी कानूनी और नियामकीय जाँच पर जोर देगी।

प्रवक्ता ने बताया कि उक्त अधिकारी ने श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या एसजी-386 के बोर्डिंग गेट पर तैनात एयरलाइंस के

चार कर्मचारियों को इतना पीटा कि एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके जबड़े में गंभीर चोट आई। जब दूसरे कर्मचारी उसे बचाने आए तो अधिकारी ने उन्हें भी पीटा।

प्रवक्ता ने कहा कि अधिकारी के सामान का वजन 10 किलोग्राम था जबकि, मुसाफिरों को विमान के अंदर केवल सात किलोग्राम ले जाने की इजाजत है।

प्रवक्ता ने कहा, "जब उनको विनम्रतापूर्वक इस बारे में बताया गया और लागू शुल्क का भुगतान के

लिए कहा गया, तो यात्री ने इन्कार कर दिया और बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी किए बिना ही जबरन एयरोब्रिज में प्रवेश कर गया। यह विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन था।" प्रवक्ता ने कहा, "सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने उसे वापस गेट तक पहुँचाया।" इस मामले में सेना ने कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगी। सेना ने बयान में कहा, हम अनुशासन के उच्च मानकों पर चलते हैं और इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं।

बद्रीनाथ हाईवे पर पुल क्षतिग्रस्त, भारी वाहनों पर रोक

चमोली, 03 अगस्त। उत्तराखण्ड के चमोली जिले मे शनिवार रात्रि को भारी वर्षा होने के कारण बदरीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी स्थित मोटर पुल के दोनों ओर की एबटमेंट सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गयी है। सतकंता और सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई

■ **हल्के वाहनों का आवागमन चालू रखा गया है तथा बद्रीनाथ यात्री भी फिलहाल जारी है।**

है।छोटे वाहनों टैक्सी, कार सहित अन्य हल्के वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। बदरीनाथ यात्रा फिलहाल जारी है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जानकारी देते हुए रविवार को बताया फिलहाल बदरीनाथ हाईवे यहाँ पर हल्के वाहनों के ही खोला गया है। पांडुकेनवर से ऊपर सभी भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है।

रीट पेपर लीक में जब्त 1.20 करोड़ की एफडी होगी

यह राशि गत चार साल से गंगापुर सिटी थाने में रखी हुई थी

जयपुर, 3 अगस्त। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 पेपरलीक मामले में जब्त 1.20 करोड़ रूपए से अधिक राशि की एफडी होगी।

ईडी मामलों की विशेष अदालत ने एसओजी को इसके निर्देश दिए हैं। यह राशि पिछले चार साल से गंगापुरसिटी थाने में रखी थी, लेकिन अब पेपरलीक का मामला जयपुर ट्रांसफर होने के बाद जब्त कैश और अन्य माल ईडी कोर्ट को भेज दिया गया।

यह राशि गंगापुरसिटी थाना पुलिस ने साल 2021-22 में अलग-अलग आरोपियों से बरामद की थी।

मामलों में विशिष्ट लोक अभियोजक बीएस चौहान ने बताया कि गंगापुर सिटी थानाधिकारी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करके जब्तशुदा एक करोड़ 20 लाख दो हजार रूपए व सामान को न्यायालय में जमा करवाने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर नकदी को एफडी में जमा करवाने का आदेश दिया, वहीं जब्तशुदा सामान एसओजी थाने को सौंप दिया।

कोर्ट ने कहा कि एफडी अधिक ब्याज देने वाले बैंक में करवाई जाए

सरयू नहर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
आया। बमुश्किल खिड़की का शीशा तोड़कर एक-एक की बाहर निकाला। तब तक सभी की मौत हो चुकी थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लेकर शोक संतप परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों को पांच लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
पत्र नहीं रख सकता है। अगर रखता है तो यह अपराध है। एनडीए के प्रवक्ताओं ने साफ कहा कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव पर मुकदमा दायर करना चाहिए।

‘साढ़े छः ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
आयोग के कथित कदम का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि यह भाजपा की उन रज्यों की वोट देने वाली आबादी का डेटा बदलने की चाल है जहाँ उसकी कोई पकड़ नहीं है।

प्रेनाइट खदान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबु नायडू ने इस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायल श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।

नई दिल्ली, 03 अगस्त। रूस से कच्चा तेल खरीदने पर आपत्ति जताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए खुशखबरी है। भारत ने पिछले तीन महीने में पिछले साल की अपेक्षा 114 प्रतिशत ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है। अगर जनवरी से 25 जून तक बात करें तो भारत ने पिछले साल की अपेक्षा अमेरिका से 51 प्रतिशत ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है। पिछले साल जनवरी से जून तक 0.18 एमबी/डी कच्चा तेल भारत में आयात हुआ था, इस साल अब तक

रही है। गर्मियों के महीनों में भी यह वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। गत जुलाई में भारत ने जून की तुलना में अमेरिका से 23 प्रतिशत ज्यादा कच्चा तेल आयात किया है। भारत के कुल कच्चे तेल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी महज 3 प्रतिशत थी, जो जुलाई में बढ़ कर 8 प्रतिशत हो गई है। सूत्रों का कहना है कि वित्तीय साल 2025-2026 में भारतीय कंपनियां अपने कच्चे तेल के आयात में 150 प्रतिशत की वृद्धि करेंगी। आयात की यह बढ़त केवल

■ **अप्रैल-जून 2024 में आयात 1.73 बिलियन डॉलर था, जो इस अप्रैल-जून में 3.7 बिलियन डॉलर हो गया।**

इसकी मात्रा .271 एमबी/डी पहुंच चुकी है। 2024 की तुलना में अप्रैल से जून 2025 तिमाही में भारत ने अमेरिका से 114 प्रतिशत ज्यादा कच्चा तेल आयात किया है। इन आयातों का वित्तीय मूल्य दोगुने से भी अधिक हो गया है। 2024-25 की पहली तिमाही में 1.73 बिलियन डॉलर से बढ़ कर 2025-26 की अप्रैल से जून में 3.7 बिलियन डॉलर हो गया है।

सूत्रों के अनुसार, कच्चे तेल के आयात की गति और तेज होती दिख

कच्चे तेल पर नहीं है। यह बढ़त अन्य इन्जनी प्रोडक्ट पर भी है। अमेरिका से भारत आने वाला तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात भी तेजी से बढ़ा है। वित्तीय साल 2024-25 में एलएनजी आयात 2.46 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 1.41 अरब डॉलर से लगभग दोगुना है। यानी एलएनजी आयात में करीब 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एयर इंडिया का पुनः “राष्ट्रीयकरण” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
विमान ऑर्डर दिया है, तकनीक और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में निवेश किया है, और ब्रांड की साख वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का बदलाव, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार भी, कई सालों में होता है, महीनों में नहीं।

आज जो समस्याएँ एयर इंडिया में देखी जा रही हैं, वे पुनर्गठन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, न कि व्यवस्था की विफलता। अभी अगर फिर से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो भारत के आर्थिक सुधारों की साख को बड़ा झटका लगेगा और वैश्विक निवेशकों का भरोसा कमजोर होगा, जिन्हें नीति में स्थिरता चाहिए।

यह बात सही है कि एयर इंडिया के साथ भावनात्मक लगाव आज भी बना हुआ है। दशकों तक यह भारत की हवाई

■ **पर, यह भी जरूरी है कि एयर इंडिया का मैनेजमेंट अपनी दिक्कतों व कमियों के बारे में सही जानकारी दे जनता को, नहीं तो यह “इम्पेशन” जोर पकड़ लेगा कि मैनेजमेंट के पास सिविल एविएशन का पूरा अनुभव नहीं है और कार्य कुशलता के अभाव में कंपनी डूब जायेगी।**

पहचान रहे हैं, प्रधानमंत्रियों को ले जाने वाली, संकेत में नागरिकों को वापस लाने वाली और प्रवासी भारतीयों को देश से जोड़ने वाली एयरलाइन। जब वही एयरलाइन निजी हाथों में संघर्ष करती दिखती है, तो लोगों को पीड़ा होती है।

अगर टाटा समूह द्वारा दी जा रही पूंजी और स्वतंत्रता के बावजूद एयरलाइन लगातार विफल होती है, तो सार्वजनिक हित की बात फिर से उठ सकती है। मनीष तिवारी की यह चिंता, कि गैर-विमानन पेशेवर (नॉन

एविएशन प्रॉफेशनल्स) ऐसे चला रहे हैं, इस बड़े भय को दर्शाती है कि एयर इंडिया की आत्मा सिर्फ लाभ कमाने के चक्कर में कहीं खो रही है।

इसके अलावा, भारत जैसे विशाल देश में हवाई संपर्क एक रणनीतिक संसाधन है। अगर निजी नियंत्रण में कुछ प्रमुख मार्ग घाटे का सौदा बनते हैं, तो जनता की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। ऐसे में सरकार को सीधे या रैग्युलेशन के जरिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।

फिर भी, एयर इंडिया का पुनः राष्ट्रीयकरण अभी जल्दबाजी होगी और

मुश्किल से हो रहे सुधारों को कमजोर कर दिया का खतरा पैदा हो सकता है। एयर इंडिया को कब्जे में लेने की नहीं, बल्कि कड़ी निगरानी की जरूरत है। सरकार को अपने नियामक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सेवा गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा पर नजर रखनी चाहिए। वहीं, टाटा समूह को संवाद बेहतर करना होगा, तेजी से कदम उठाने होंगे और यात्रियों व नीति-निर्माताओं, दोनों को यह भरोसा दिलाना होगा कि वे इस जिम्मेदारी के लायक हैं।

निजीकरण कभी कोई जादू की छड़ी नहीं था। यह एक ऐसा कदम था, जिससे सरकार को एयरलाइन चलाने के काम से आज़ाद किया जा सके, ताकि वह शासन पर ध्यान दे सके। इसी भावना में, जरूरी है कि जो टूटा है, उसे ठीक किया जाए, बिना उसे फिर से पूरी तरह बिगाड़े।